राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक: 29.11.2023
स्थान– होटल रैडिसन ब्लू

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 85वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 85वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक 29.11.2023 को होटल रैडिसन ब्लू , राँची के GBR सभागार में आयोजित की गई। बैठक में माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार, डॉ रामेश्वर उरांव मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय से कार्यपालक निदेशक श्री सुब्रत कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग, झारखंड सरकार के प्रधान सचिव, श्री अजय कुमार सिंह,भा॰प्र॰ से॰, एस.एल.बी.सी झारखंड के संयोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक, रांची क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, नाबार्ड झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक, श्री सुनील कृष्णा जहांगीरदार, निदेशक वित्त विभाग, झारखंड सरकार के श्री रमेश घोलप,भा॰प्र॰से॰, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के श्री सय्यद रियाज़, भा॰प्र॰से॰, एस॰एल॰बी॰सी के उप महाप्रबंधक, श्री अनिल जगदीश जाधव, भारतीय रिजर्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय के उप महाप्रबन्धक श्री बिनोद मिश्रा उंपस्थित थे। इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री प्रभास बोस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री बैजनाथ सिंह, कैनरा बैंक के महाप्रबंधक श्री श्रीनाथ जोशी अथवा अन्य सभी बैंकों के राज्य प्रमुख तथा सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं केंद्र/राज्य सरकार के अन्य विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक के क्रम मे सभा अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न प्रमुख गणमान्यों को सभा सम्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया,जिनकी प्रस्तुति निम्नतः है-

क) **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार का सम्बोधन-**

- श्री मनोज कुमार ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं बैंकों के सितम्बर तिमाही के प्रदर्शन,अन्य नीतिगत मुद्दे एवं महत्वपूर्ण विषयो के संबंध मे सभा का ध्यान आकृष्ट किया।
- महाप्रबंधक एस॰एल॰बी॰सी॰ ने माननीय मंत्री एवं भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक को आश्वस्त किया की, झारखंड राज्य के सभी बैंक मिलकर ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को पूर्ण रूप से केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान कर रहे है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री कुमार ने सभा को बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित- 92,935 करोड़ रूपय के लक्ष्य के विपरीत बैंकों द्वारा 30 सितम्बर 2023 तक 53,922 करोड़ रूपय का ऋण वितरण किया गया है, जो की ACP TARGET का 58.02% रहा।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री कुमार ने बताया की राज्य में ऋण जमा अनुपात में सुधार के उद्देश्य से DFS के निर्देशानुसार राज्य के 5 CREDIT DEFICIT जिलों: *गुमला, चतरा, सिमडेगा, पाश्चिमी सिंघभूम, जामतारा* में 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2023 (90 दिनों) तक credit outreach प्रोग्राम चलाया गया।

  उन्होने ने बताया की इस अभियान के तहत 30 सितम्बर तक कुल 20,306 लाभूकों को 536.88 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया, जिसके फल स्वरूप तीन जिलों (गुमला, चतरा, सिमडेगा) के ऋण जमा अनुपात में वृद्धि दर्ज की गयी। हालांकि पश्चिमी सिंघभूम और जामतारा जिलों में यह वृद्धी नहीं दर्ज की जा सकी। श्री कुमार ने दोनों अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों को और अधिक ऋण वितरण पर कार्य करने की बात रखी।

  (एक्शन- पश्चिमी सिंघभूम और जामतारा जिले)

- महाप्रबंधक एल॰एल॰बी॰सी ने सभी अग्रणी जिला प्रबन्धको से आग्रह किया की वे क्रेडिट component को बढ़ाने के लिए अपने – अपने ज़िले में एक या उससे अधिक ऋण उत्पाद पहचाने जिसकी आवश्यकता और संभावना उस क्षेत्र में हो तथा उसी ऋण उत्पाद पर ज़ोर दें।

  (एक्शन- समस्त एल.डी.एम)

- श्री कुमार ने राज्य में एनपीए में आई गिरावट के लिए सभी बैंको की सराहना की। उन्होने बताया की बैंकों द्वारा दिये गए कुल ऋण के NPA होने मे वर्ष दर वर्ष 16.50 प्रतिशत की गिरावट आई है जो की राज्य एवं बैंक के लिए अच्छे संकेत है।

  (एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री कुमार ने एस॰एल॰बी॰सी द्वारा चलाई जा रही Village adoption –phase II कार्यक्रम के बारे में सभा को संबोधित की। उन्होने बताया की इस कार्यक्रम के तहत राज्य के ग्रामीण एवं अर्ध शहरी शाखाओं द्वारा 1900 से भी अधिक गाओं को गोद लिया गया है, किन्तु उन्हे किसी भी एक बैंकिंग सुविधा से संतृप्त करने का कर्य अभी शेश है। उन्होने सभी एलडीएम और राज्य प्रमुखों से आग्रह किया की वे इस कार्य को तीव्र गति प्रदान करे और मार्च, 2024 तिमाही तक इस कार्य को पूर्ण करें।

  (एक्शन-समस्त बैंक एवं एल.डी.एम)

- श्री मनोज कुमार ने अपने अभिभाषण में सभा को RSETI के बारे में बताया। उन्होने बताया की RSETI हमारे देश के गावों में बसे युवाओं को कुशल बनाने मे अहम भूमिका निभा रहे हैं, किन्तु इन प्रशिक्षित युवाओं को स्समय आर्थिक सहायता मिलने मे अभी कमी आ रही है। उन्होने सभा में उपस्थित बैंकों के राज्य प्रमुखों से आग्रह किया की वे अपनी शाखाओं में लंबे समय से लंबित आवेदनों का निपटान जल्द से जल्द करवाएँ।

  उन्होने एलडीएम से भी अनुरोध किया की वे अपने अपने आंचलिक कार्यालए से संपर्क कर उन्न क्षेत्रों के शाखा प्रबन्धकों को मध्यावधि प्रशिक्षण के दौरान बुलाकर, ऋण के संदर्भ में उन्हे जागरूक करे और valediction के दिन sanction पत्र प्रदान करे।

  (एक्शन- समस्त एल.डी.एम)

- श्री कुमार ने अपने सम्बोधन में सभा को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार राज्य के सभी 22 जिलो को 100 प्रतिशत digitalize करने की बात से अवगत कराया। उन्होने बताया की केंद्रीय कार्यालय आरबीआई के निर्देशानुसार झारखंड के सभी जिलों को 31मार्च,2024 तक 100 प्रतिशत digitalize करना है।

  उन्होने आगे बताया की झारखंड राज्य में रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले पहले ही 100 प्रतिशत digitalise हो चुके हैं, इसके अतिरिक्त सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को उक्त कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और उनकी भूमिका इस योजना को सफल बनाने में काफी अहम है। श्री कुमार ने सभी

राज्य प्रमुख अथवा एलडीएम से आग्रह किया की वे सभी बचत एवं चालू खातों के 100% डिजिटलीकरण के बारे में शाखाओं को संवेदनशील बनाए साथ ही साथ जनता को भी डिजिटल उत्पादों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करे।

(एक्शन-समस्त बैंक एवं एल.डी.एम)

- महाप्रबंधक एस॰एल॰बी॰सी॰ ने सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि वे अपने ज़िला व ब्लॉक स्तरीय की सभी त्रैमासिक बैठकों को ससमय कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होने बैंक के राज्य प्रमुखों से भी अनुरोध किया की वे अपने बैंक के district coordinators/branch managers को निर्देशित करें की ज़िला व ब्लॉक स्तरीय सभी बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे।

(एक्शन- समस्त एल.डी.एम)

अंत में श्री मनोज कुमार ने भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकार, NABARD को उचित मार्गदर्शन व अन्य हितधारकों के परस्पर सहयोग के लिए धन्यवाद प्रदान किया।

ख) **नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुनील कृष्णा जहांगीरदार का सम्बोधन-**

- श्री जहांगीदार ने सभा को बताया की नाबार्ड राज्य सरकार के साथ मिलकर PACs कंप्यूटरीकरण Program पिछले 6 महीनों से चला रही है। श्री जहांगीदार ने बताया की उन्हे ये बताने में अत्यंत खुशी हो रही है की झारखंड राज्य में 4000 PACs में से 1500 PACs पूरी तरह onboard हो चुके है PACs कंप्यूटरीकरण के लिए और इन में से 546 PACs live स्टेज में हैं। उन्होने आगे बताया की कंप्यूटरीकरण का लाभ आने वाले दिनों में दिखेगा क्यूंकि भारत सरकार आने वाले दिनो में पेट्रोल पम्प, गॅस एजन्सि, जन औषधि केंद्र, राशन की दुकाने इत्यादि आने वाले दिनों में PACs के माध्यम से देना चाहती है अतः मुख्य महाप्रबंधक ने इसे बैंकों के लिए एक अवसर बताया और कहा की राज्य के बैंक इन PACs को working Capital ऋण प्रदान कर सकते हैं।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री जाहिंगदार ने अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भारत सरकार की आगामी योजना के बारे में सदन को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत, झारखंड सरकार ने 5 जिलों-बोकारो, गुमला, लातेहार, गिरिडीह और साहेबगंज में 500-750 मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण की मंजूरी दे दी है।

  इसी क्रम में उन्होने आगे बताया कि झारखंड राज्य में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 47.61 लाख मीट्रिक टन पिछले वर्ष हुई है जबकि भंडारण क्षमता लगभग 5.71 लाख मीट्रिक टन है जो कि राज्य द्वारा उत्पादित भंडारण क्षमता का केवल 11-12% है, वहीं छतीसगढ़ में 110 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता के विपिरित भंडारण क्षमता 49 लाख मीट्रिक टन है जो की 44 प्रतिश के करीब है। इस संबंध में श्री जाहिंगदार ने कहा कि झारखंड राज्य में ग्रामीण गोदाम निर्माण में ऋण प्रदान की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि वे जरूरतमंदों को ऋण स्वीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करें इससे राज्य में दीर्घकालिक कृषि ऋण (long-term agriculture lending) में काफी सुधार होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना में भारत सरकार द्वारा 25-33% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने 01 अक्टूबर, 2023 से शुरू किए गए घर-घर केसीसी अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उक्त अभियान के तहत राज्य में बैंको की प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने

सदस्य बैंकों से आग्रह किया कि वे अपनी शाखाओं को 31 दिसंबर, 2023 के अंत तक केसीसी ऋण के माध्यम से सभी पीएम किसान को 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने का निर्देश दें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री जहांगीदार ने कहा कि झारखंड राज्य में बांस के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने हाल ही में रांची में हुई क्षेत्रीय सलाहकार समूह की बैठक का जिक्र किया, जिसमें ओरिएंट पेपर मिल के साथ विशेषज्ञों को भी बैठक में बुलाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसानों, बैंकों और पेपर मिल के बीच त्रिपक्षीय समझौता हो जाए तो इससे किसानों और बैंक दोनों को फायदा होगा। श्री जहाँगीर ने ख़ुशी ज़ाहिर करते हुए बताया कि ओरिएंट पेपर मिल के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया है कि, मिल उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी बांस की ख़रीदारी करने को तैयार है। उन्होंने बांस के अर्थशास्त्र को भी सभा को समझाया और कहा कि यदि 10 एकड़ में बांस की खेती की जाए, तो 10 वर्षों के अंत तक कुल मुनाफा लगभग 70 लाख रुपये का होगा, जबकि अगर किसान अनाज की खेती करता तो यह मुनाफा मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ होगा।

  उन्होंने आश्वासन दिया कि नाबार्ड ओरिएंट पेपर मिल के साथ त्रिपक्षीय समझौते का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि ओरिएंट पेपर मिल के साथ एक औपचारिक बैठक कर समझौते को औपचारिक रूप देने की कोशिश करे, जिसके उपरांत सभी बैंकों उसे निष्पादित कर सकें।

(एक्शन- नाबार्ड और एसएलबीसी)

- श्री जहांगीदार ने पी.एम.एफ.एम.ई योजना के तहत कम वित्तपोषण का मामला सभा में उठाया ,उन्होने कहा कि बैंक उक्त योजना के तहत नई इकाई स्थापित करने के लिए 5-10 लाख रुपये का ऋण प्रदान कर रहे है, किन्तु यह देखा गया है कि इसके उपरांत भी नये उद्यमियों को अपने खाद्य उत्पादों के विपणन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वहीं कुछ मौजूदा इकाई हैं जो परंतु उनका बैंकों द्वारा वित्तपोषन नहीं किया गया है।

  उन्होने एसएलबीसी अथवा पीएमयू को सुझाओ दिया की वे ऐसी इकाइयों का चयन करें जो मौजूदा इकाई हो और उन्हे वित्तपोषण की अवशकता हो , क्यूंकी उन्हे बैंकों द्वारा वित्तपोषण कर ,व्यापार बढ़ाने की उचित संभावनाएं हैं।

(एक्शन- एसएलबीसी)

- नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि झारखंड में भारी मात्रा में लाख/लाह का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में लाख का 60 प्रतिशत उत्पादन झारखंड राज्य से होता है, लेकिन उक्त उत्पाद के तहत वित्त (Scale of Finance) का कोई पैमाना नहीं था, हालाँकि, उन्होने बताया की पिछली तकनीकी समिति की बैठक में नाबार्ड ने लाख की खेती के लिए वित्त (Scale of Finance) का पैमाना तय कर दिया गया है । उन्होने बैंकों को इस उत्पाद के अंतर्गत वित्तपोषन करने की सलाह दी।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री जहांगीदार ने सदन को रांची में आयोजित *क्लासिल्क प्रदर्शनी* के बारे में जानकारी दी, उन्होने बताया की उक्त प्रदर्शनी के दौरान 10 दिनों में 10 करोड़ रुपये की बिक्री हुई ,ये सभी उत्पाद हथकरघा और रेशम के थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में शिल्प और राज्य के उत्पादों की अपार संभावनाएं हैं, जिसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री जहांगीदार ने RIDF योजना में समर्थन के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया उन्होने विशेषकर माननीय वित्त मंत्री जी को RIDF के अंतर्गत ऋण उपभोग करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस वर्ष पहले ही विभिन्न परियोजनाओं में नाबार्ड द्वारा 1044 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके है ,इसके अतिरिक्त उन्होने यह भी बताया कि 1500 करोड़ रुपये का परिव्यय तैयार किया जा चुका है जिसे झारखंड सरकार के समक्ष रखा जाएगा।

  उन्होंने माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि नाबार्ड के पास NIDA फंड (NABARD Infra Development Assistance) भी है जिसका उपयोग राज्य सरकार राज्य के विकास के लिए कर सकती है, उन्होने बताया की यह फंड RIDF की तरह ही है।

  (एक्शन- राज्य सरकार)

ग़) भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह का सम्बोधन

- श्री भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने इस 85वीं एसएलबीसी बैठक में सभी हितधारकों का स्वागत किया और कहा कि उन्हें इस महत्वपूर्ण बैठक में पहली बार संबोधित करते हुए अत्यंत खुशी ज़ाहिर करी।
- श्री सिंह ने बताया कि राज्य में बैंकिंग कार्य निष्पादन के संदर्भ में, उन्हे यह जानकर खुशी हुई है कि सितंबर 2023 की समाप्त तिमाही के दौरान राज्य के लिए अग्रिम ऋण का आँकड़ा 1 लाख करोड़ रुपये की उच्चत्तर सीमा को स्पर्श कर गया है। इस अथक और निरंतर प्रयास के लिए उन्होने सभी बैंकों को बधाई दिया और कहा की उन्हे विश्वास है कि विकास की यह गति आगे भी बनी रहेगी।

  उन्होने आगे अपने वक्तव्य में बताया की 30 सितंबर, 2023 तक राज्य का ऋण जमा अनुपात 45.04 प्रतिशत रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 4.66% की वृद्धि दर्शाता है। उन्होने बैंकों को ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा।

  (एक्शन- समस्त बैंक)
- क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई ने बताया की 30 सितंबर, 2023 तक राज्य की वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) उपलब्धि 58.02 प्रतिश रही साथ ही साथ उन्होने कहा की समग्र स्तर पर उपलब्धि संतोषजनक प्रतीत होती है किन्तु उन्होने कहा की अलग-अलग आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सदस्य बैंकों द्वारा उपलब्धि असमान (11% से 181% तक) है और जिन बैंकों की उपलब्धि 50% से कम है, उन्हें व्यापक तौर पर ऋण देने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने और मौजूदा वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान अपने संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ज़ोर दिया।

  (एक्शन- समस्त बैंक)
- श्री सिंह ने सभा को वित्तीय समावेशन के बारे में बताया उन्होने कहा की वित्तीय समावेशन न केवल इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि समृद्धि व्यापक रूप से साझा की जाए। उन्होने आगे बताया की वित्तीय समावेशन को समग्र तरीके से मापने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक (Financial Inclusion Index) का निर्माण किया गया है, जिसमे वित्तीय समावेशन के तीन आयामों अर्थात पहुँच (Reach), उपयोग (Utilization) और गुणवत्ता (Quality) को समाहित किया गया है।

श्री सिंह ने अपने वक्तव्य में आगे कहा की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक को वर्ष 2021, 2022 और 2023 के लिए प्रकाशित किया गया है और एफआई सूचकांक की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि झारखंड राज्य के 08 ज़िले (*चतरा, गढ़वा, गुमला, जामतारा, खूँटी, पाकुर, साहेबगंज एवं सिमडेगा*) वित्तीय समावेशन के पहुँच मापदंड के तहत (*अर्थात शाखाओं/स्थायी बीसी और एटीएम की उपस्थिति के अनुसार*) प्रति व्यक्ति वितरण के निचले 10 प्रतिशत की श्रेणी में आते हैं। उन्होने इस संबंध में बैंकों से यह अनुरोध किया की इन ज़िलों में पहुँच मापदंड अर्थात शाखाओं/स्थायी बीसी और एटीएम की उपस्थिति में सुधार लाने हेतु ठोस कदम उठाने की अवशकता है। इसके पश्चात उन्होने एसएलबीसी से आग्रह किया कि वे इसकी निगरानी अपने स्तर पर करे और इसकी मासिक प्रगती रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित करे।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एसएलबीसी)

- क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के योगदान एवं उद्यमी पंजीकरण की स्थिति के बारे में सभा को अवगत कराया। उन्होने बताया कि अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे देश के विकास इंजन के रूप में माना जाता है, जो सकल घरेलू उत्पाद और व्यापार में योगदान देने के अलावा, आबादी के बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करते हैं। उन्होने सभी बैंकों और संस्थानों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को अधिक महत्व देने कि बात कही, क्योंकि यह भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने एवं वर्ष 2047 तक विकसित देश के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में मदद करेगा।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सिंह ने बताया कि राज्य स्तर पर सूक्ष्म इकाइयों की कुल संख्या सितंबर 2022 के 5.92 लाख से बढ़कर सितंबर 2023 तक 6.35 लाख हो गई है उन्होने कहा कि सूक्ष्म इकाइयों की संख्या में यह वृद्धि मुख्य रूप से उद्यम पंजीकरण पोर्टल के तहत पंजीकरण की संख्या में वृद्धि के कारण है। उन्होने आगे बताया कि प्रधानमंत्री कार्यबल (पी.एम.टी.एफ) के अनुरूप सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10% वार्षिक वृद्धि लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका और सितंबर 2023 तक यह 7% पर रही। उन्होने बैंक से आग्रह किए कि वे इस लक्ष्य को हासिल करने कि कोशिश करे।

  श्री सिंह ने कहा कि उद्यमी पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के संबंध में प्रमुख बैंकों से नियमित आश्वासन के बावजूद, राज्य में सूक्ष्म उद्यमों की संख्या में 10% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है। अतः उन्होने बैंकों के राज्य प्रमुखों से यह अनुरोध किया कि वे उद्यमी पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के संबंध में ठोस कदम उठाए।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सिंह ने सभा को बताया कि वैसे सूक्ष्म उद्यम जिनके पास उपयुक्त कागजात उपलब्ध नहीं है, उनके लिए भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) (Informal Micro Enterprises) को औपचारिक बनाने की सुविधा के लिए *उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म* (यूएपी) लॉन्च किया है। उन्होने आगे बताया कि आईएमई वे उद्यम हैं जो वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में शामिल नहीं हैं। उद्यम सहायता प्रमाणपत्र वाले आईएमई को पीएसएल वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए एमएसएमई के तहत सूक्ष्म उद्यमों के रूप में माना जाएगा। अतः उन्होने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में सूक्ष्म उद्यमों को जागरूक करे एवं पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाएँ।

(एक्शन- समस्त एलडीएम एवं बैंक)

- भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने सभा को पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया ,उन्होने कहा कि दिनांक 17 सितंबर 2023 को भारत सरकार ने **'पीएम विश्वकर्मा योजना'** का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने संबंधित व्यापार की मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकें। उन्होने बताया कि इस योजना में, अन्य उपायों के अलावा, लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान सहायता के साथ रियायती ब्याज दर पर ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है। श्री सिंह ने बैंकों से अनुरोध किया कि वे इस योजना के बारे में लोगों कों जागरूक करें एवं लाभार्थियों को चिन्हित कर रियायती ब्याज दर पर ऋण सहायता प्रदान करे।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सिंह ने अपने सम्बोधन में सभा को व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली (Trade Receivable Discounting System-TReDS) के बारे में बताया। उन्होने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई TReDS प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य MSMEs की महत्त्वपूर्ण ज़रूरतों जैसे-तत्काल प्राप्यों का नकदीकरण और ऋण जोखिम को समाप्त करने वाले दोहरे मुद्दों का समाधान करना है। उन्होने आगे बताया कि TReDS प्लेटफॉर्म, एक नीलामी तंत्र द्वारा सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित बड़े कॉर्पोरेटों के समक्ष MSMEs के विक्रेताओं के बीजक/विनिमय बिलों के बट्टाकरण (Discounting) में सहायता प्रदान करता है इससे प्रतिस्पर्द्धात्मक बाज़ार दरों पर व्यापार प्राप्यों की त्वरित वसूली सुनिश्चित होती है।

उन्होने आगे कहा कि एमएसएमई पर अधिकार प्राप्त समिति की 60वीं बैठक में भारतीय स्टेट बैंक ने अवगत कराया था कि बैंक ने जमशेदपुर की एक शाखा को टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर कार्यशील किया है, उन्होने अन्य बैंकों से भी झारखंड राज्य में अपनी शाखाओं को टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर कार्यशील बनाने की कार्ययोजना प्रदान करने का आग्रह किया साथ ही साथ उन्होने राज्य सरकार से भी अनुरोध किया कि वे सरकारी विभागों को क्रेता के तौर पर टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर पंजीकरण लेने हेतु प्रेरित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं राज्य सरकार)

- श्री सिंह ने वित्तीय साक्षरता पर सभा को सम्बोधन करते हुए कहा की अग्रणी बैंकों और आरआरबी द्वारा नियुक्त, वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) परामर्शदाताओं ने 30.09.2023 तक 1036 शिविर आयोजित किए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के दौरान 1450 शिविर आयोजित किए गए थे। उन्होने आगे कहा की प्रायोजक बैंकों द्वारा चार जिलों क्रमशः *गिरिडीह, सिमडेगा, लोहरदगा और रांची* में एफएलसी परामर्शदाताओं की नियुक्ति नहीं हो पायी है तथा उन्होने प्रायोजक बैंक से एफएलसी परामर्शदाताओं के रिक्त पद को जल्द से जल्द भरने का अनुरोध किया।

(एक्शन- बैंक ऑफ इंडिया)

- उन्होने राज्य सरकार और झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से वित्तीय साक्षरता की कार्यपुस्तिकाओं के 59 विशिष्ट अध्यायों में से शेष 37 अध्यायों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का पुनः आग्रह किया और बताया की इससे विभिन्न हितधारकों के द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए किए जा रहे प्रयासों को गति मिलेगी।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- श्री सिंह ने कहा की वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक कई तरह के प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में वित्तीय साक्षरता और जन जागरूकता की एक नयी पहल के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची कार्यालय ने आज़ादी के अमृत पर्व और अमृत काल के शुभ अवसर पर 75 नवरचित सुभाषितों (स्लोगन)

की अनूठी पुस्तिका प्रकाशित की है। उन्होने आगे बताया की वित्तीय समावेशन, जन जागरण, पर्यावरण व राजभाषा कार्यान्वयन सदृश महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़े सरल भाषा में रचे ये स्लोगन पूरे देश भर में रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों व अन्य संस्थानों के वित्तीय शिक्षण व साक्षरता, जागरूकता संबंधी अभियानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री सिंह ने बताया की गाँधी जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक,राँची क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा अभिनव पहल के रूप में *'गाँधी जी और हम'* विषय पर राज्य के सभी स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने गाँधी जी से जुड़े प्रेरक प्रसंग एवं उनके विचार जो वे जीवन में अपनाना चाहते हैं, पर अपनी प्रविष्टियाँ प्रस्तुत कीं। इस पहल से विद्यार्थी अत्यंत उत्साहपूर्वक जुड़े और कुल चार सौ से अधिक निबंध प्राप्त हुए। उन्होने कहा की समग्र मूल्यांकन के पश्चात प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान तथा प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- क्षेत्रीय निदेशक ने कहा की झारखंड राज्य में डिजिटल भुगतान प्रणाली तंत्र के विस्तार और वृद्धि के उद्देश्य से रांची और पूर्वी सिंहभूम जिलों की पहचान की गई थी एवं उन्होने यह बटाये हुए अपनी खुशी जाहीर की कि दोनो जिले को 100 प्रतिशत डिजिटल रूप से सक्षम बना लिया गया है।

  उन्होने आगे बताया की इसकी अगली कड़ी में झारखंड राज्य के शेष 22 जिलों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए 31 मार्च 2024 का लक्ष्य रखा गया है और उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए एवं इसकी मासिक प्रगति रिपोर्ट एसएलबीसी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित करे।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सिंह ने एमएसएमई सर्वेक्षण के बारे में सभा को संबोधित किया। उन्होने कहा की औपचारिक क्रेडिट लिंकेज की वर्तमान स्थिति और वित्त तक पहुंच में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों की व्यापक समझ हासिल करने के लिए, एमएसएमई का एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण आरबीआई द्वारा किया जा रहा है तथा इस सर्वेक्षण का उद्देश्य औपचारिक क्रेडिट लिंकेज की स्थिति और वित्त तक पहुंच से संबंधित विभिन्न पहलुओं, आरबीआई के निर्देशों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और एमएसएमई के सामने आने वाली नियामक चुनौतियों का आकलन करना है। उन्होने आगे बताया की अध्ययन में 10000 एमएसएमई इकाइयों का राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शामिल है और झारखंड राज्य में 251 ऐसी एमएसएमई इकाइयों का सर्वेक्षण किया जा रहा है अर्थात उन्होने कहा की ये सर्वेक्षण के नतीजे हमें इस क्षेत्र में हमारी नीतिगत पहलों को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। उन्होने इस सर्वेक्षण को सफल बनाने की लिए सभी हितधारकों का सहयोग मांगा।

(एक्शन- समस्त एलडीएम एवं बैंक)

- अंत में, उन्होने कहा की हमने एक लंबा सफर तय किया है किन्तु अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। उन्होने कहा की एसएलबीसी कारोबारी सत्र में पिछले एसएलबीसी बैठक से उत्पन्न कार्रवाई बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई को संक्षेप में कवर करे, क्यूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सदस्य बैंक समिति द्वारा दिए गए निर्देशों/सुझावों पर समयबद्ध तरीके से कार्य करे ताकि बैठक के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

(एक्शन- एसएलबीसी)

घ) अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, झारखंड सरकार, श्री सैय्यद रियाज़ का सम्बोधन

- श्री सैय्यद रियाज़ ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की और से झारखंड सरकार की महत्वाकांशी योजना "गुरु जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम" के बारे में सभा के सदस्यों को जानकारी प्रदान की।
- उन्होंने कहा कि यह योजना उन छात्रों के लिए शुरू की गई है जो मेधावी हैं लेकिन वित्तीय कारणों से अच्छे संस्थानों में पढ़ने में असमर्थ हैं। उन्होंने आगे बताया कि बैंकों और एसएलबीसी से चर्चा के बाद एक गाइडलाइन तैयार की गई, जिसे कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गयी है।

  उन्होने आगे बताया की यह योजना बैंकों द्वारा संस्थागत और गैर-संस्थागत खर्चों को मिला कर , अधिकतम 15 लाख रुपये तक के वित्तपोषण को कवर करेगी इसके अलावा उन्होने सभी सदस्यो को गुरु जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
- श्री सैय्यद रियाज़ ने सदन को बताया कि इस योजना की पूरी प्रक्रिया वेब पोर्टल के माध्यम से होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि एचडीएफसी बैंक उक्त योजना के लिए कॉर्पस बैंक की भूमिका निभा रही है।
- उन्होंने आगे बताया कि उक्त योजना के अंतर्गत छात्रों को केवल 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा बाकी राज्य सरकार वहन करेगी जिसके अंतर्गत ब्याज सब्सिडी की राशि संबंधित बैंकों को त्रैमासिक वितरित की जाएगी।

अंत में श्री सैय्यद रियाज़ ने सदस्य बैंकों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे इस योजना को उनके प्रधान कार्यालय द्वारा जल्द से जल्द मंजूरी दिलवाएँ , साथ ही उन्होने बताया की योजना का विवरण पहले ही सदस्य बैंकों के साथ साझा किया जा चुका है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

ङ) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, श्री अजय कुमार सिंह का सम्बोधन

- वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में कहा कि एसएलबीसी की बैठक राज्य सरकार एवं बैंको के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है जहां हम सब मिलकर राज्य के वेहतरी के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत रूपरेखा बनाने पर चर्चा करते है।
- श्री सिंह ने क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बारे में सदन को जानकारी दी, जिसकी अध्यक्षता माननीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। उन्होंने बताया कि उक्त बैठक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है: 3000 से अधिक आबादी वाले ऐसे गांव जहां 05 किमी के दायरे में कोई ब्रिक अँड मोर्टर शाखा नहीं है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में अभी भी 6 स्थान/गांव ऐसे हैं जहां की आबादी 3000 से अधिक है और 5 किमी के दायरे में कोई ब्रिक एंड मोर्टर शाखा नहीं है। श्री सिंह ने बताया कि हम पिछले एक साल से इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन अब तक हम इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होने बताया की ये 06 स्थान: गढ़वा में 04, गिरिडीह में 01 और सेराईकेला में 01 है।

  वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने सदन को आश्वासन दिया कि यदि कोई बैंक पंचायत भवन में अपनी शाखा खोलना चाहता है, तो सरकार उक्त परिसर में नि:शुल्क जगह उपलब्ध कराएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई कनेक्टिविटी समस्या हो, सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो तो हम उसका ध्यान रखेंगे।

  उन्होंने सदस्य बैंकों से 31 दिसंबर, 2023 तक आवंटित स्थान पर सकारात्मक रूप से बैंक शाखाएं खोलने का आग्रह किया।

(एक्शन- UBI, CBI, IDBI, INDUSIND, BOM & UCO)

- श्री सिंह ने कहा कि 3000 से कम आबादी वाले स्थानों को या तो बैंकिंग संवाददाता या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाओं द्वारा कवर किया जाना है। उन्होंने आगे बताया कि 1962 स्थानों में से 1680 स्थानों को बैंकिंग चैनल के माध्यम से कवर किया जा चुका है, किन्तु 282 स्थान अभी भी ऐसे है जिनहे कवर किया जाना बाकी है। उन्होंने सदस्यों से इन स्थानों को जल्द से जल्द कवर करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त एलडीएम एवं बैंक)

- श्री सिंह ने झारखंड सरकार द्वारा सभी गांवों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए उठाये गये कदमों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग ने सभी पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के साथ एक समझौता किया है साथ ही साथ सीएससी को बैंकिंग समन्वयक के रूप में काम करने का अधिकार दिया गया है और इसके एवज में झारखंड सरकार उन्हें मासिक भुगतान भी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि बीसी प्वाइंट खोलने की जिम्मेदारी सीएससी की है, किन्तु इसे लागू करने के लिए बैंक से समर्थन की आवश्यकता है। उन्होंने एसएलबीसी, बैंक से इसके कार्यान्वयन के लिए सीएससी और पंचायती राज विभाग के साथ बैठक कर योजना बनाने का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक, एसएलबीसी एवं राज्य सरकार)

- उन्होंने अपने भाषण में कहा कि राज्यों में कई छात्रों के पास बैंक खाते नहीं हैं, जिसके कारण जब सरकार छात्रवृत्ति की राशि वितरित करती है तो बैंक खाता न होने के कारण उन्हें वह राशि नहीं मिल पाती इसके लिए, उन्होंने बैंकों से शिविर के माध्यम से छात्रों के खाते खोलने पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया और कहा की यदि ये कार्य हो जाती है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सिंह ने राज्य के ऋण जमा अनुपात का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड और पूर्वी भारत के राज्यों का ऋण जमा अनुपात काफी खराब है अथवा इसके सुधार में समय लगेगा किन्तु राज्य का ऋण जमा अनुपात में सुधार के लिए उन्होने अगले 5 से 10 वर्षों के लिए एक ठोस दीर्घकालिक दूरदर्शी दस्तावेज तैयार करने की सलाह दी जिसके अंतर्गत यह दीर्घकालिक दूरदर्शी दस्तावेज़ राज्य को एक लक्ष्य प्रदान करेगा जिसके अनुसार राज्य को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

  उन्होंने राज्य के लिए वार्षिक ऋण योजना तैयार करते समय एक दीर्घकालिक दूरदर्शी दस्तावेज तैयार करने पर जोर दिया, जो वर्ष 2030 के अंत तक राष्ट्रीय औसत के अनुरूप राज्य के ऋण जमा अनुपात को प्राप्त करने का लक्ष्य प्रदान करेगी।

(एक्शन- नाबार्ड, एसएलबीसी एवं समस्त बैंक)

- श्री सिंह ने एसएलबीसी को वृद्धिशील (incremental) ऋण जमा अनुपात पर तैयारी करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राज्य के जमा, अग्रिम और ऋण जमा अनुपात में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि/गिरावट की तुलना की जानी चाहिए, इससे सटीक वृद्धि को समझने में मदद मिलेगी।

(एक्शन- एसएलबीसी)

- प्रधान सचिव ने राज्य सरकार द्वारा उठाए कुछ प्रमुख पहल के बारे में सदन को अवगत कराया। उन्होने ने गुरु जी क्रेडिट कार्ड के बारे में विस्तार से अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा बताई गई बातों का उल्लेख सभा के समक्ष रखा और सभी सदस्य बैंकों से इस पर अमल करने की बात रखी।

  इसके पश्चात श्री सिंह ने बताया की आने वाले समय में केसीसी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को ब्याज में अतिरिक्त एक प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी जिसके उपरांत किसानो को 7 प्रतिशत में मिलने वाले केसीसी ऋण interest free हो जायेंगे। उन्होने बताया की

इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से 3 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 4 प्रतिशत का ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी जिसे पाने के लिए किसानों को ससमय ऋण चुकाने की अवशकता होगी। उन्होने बैंकों से आग्रह किया की वे किसानों को इन मुद्दे पे जागरूक बनाए ताकि किसान इसकी पूरी तरह से लाभ ले सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सिंह ने 15 नवंबर, 2023 को झारखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई नई एमएसएमई नीति के बारे में सदन को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले राज्य में एक उद्योग नीति, यानी झारखंड निवेश और प्रोत्साहन नीति (JIPP) थी जो पूरे उद्योग को कवर करती थी, हालांकि, इस बार राज्य सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष रूप से नीति बनाई है जिसके तहत पूंजीगत सब्सिडी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। उन्होने आगे कहा कि जब कोई एमएसएमई उद्यमी झारखंड राज्य में अपनी इकाई स्थापित करता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी मिलने का प्रावधान है और यह सब्सिडी देश के किसी भी राज्य के एमएसएमई नीति में सबसे अधिक है इसके साथ ही उन्होने बैंक और अग्रणी जिला प्रबंधकों से राज्य के लोगों के बीच इस नई एमएसएमई नीति को बढ़ावा देने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- अंत में श्री सिंह ने अपने भाषण को समाप्त करते हुए सदस्य से अनुरोध किया कि विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करते समय इस बात का उल्लेख भी करें कि वे राज्य सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, यदि राज्य के विकास के लिए नई नीति बनाने की आवश्यकता होगी तो हम निश्चित रूप से इस दिशा में काम करेंगे इसके साथ ही उन्होंने राज्य के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन समस्त सदस्यो को दिया।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

च) माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार, डॉ. रामेश्वर उराँव का सम्बोधन

- माननीय वित्त मंत्री ने अपने प्रारंभिक भाषण में झारखंड राज्य के विकास के लिए 85 वीं एसएलबीसी फोरम में उठाए जाने वाले सही मुद्दे का चयन करने के लिए पहले के वक्ताओं की प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा कि हम त्रैमासिक रूप से इस मंच पर मिलते हैं और हितधारकों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा करते हैं साथ ही साथ अपने राज्य के लोगों के विकास के लिए नयी नीति भी बनाते हैं।
- डॉ. उराँव ने राज्य में ऋण जमा अनुपात का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उक्त अनुपात में साल-दर-साल बढ़ोतरी तो हो रही है किन्तु विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि राज्य में मुख्य रूप से ऋण प्रवाह शहरी क्षेत्र में हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड राज्य की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है और यह क्षेत्र झारखंड राज्य के समग्र विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने बैंकों से राज्य के समग्र विकास के लिए मजदूरों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने एवं राज्य का समग्र विकास करने के लिए, डॉ.रामेश्वर उराँव ने कहा कि घर-घर केसीसी अभियान एक अच्छी पहल है। उन्होंने बैंक और एलडीएम से घर-घर केसीसी अभियान पर ध्यान केंद्रित कर इसे सफल बनाने को कहा।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- माननीय वित्त मंत्री ने झारखंड राज्य में बढ़ते साइबर धोखाधड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वित्तीय साक्षरता एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, इस संबंध

में उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक और सदस्य बैंकों से शिविर के माध्यम से लोगों को साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूक करने की सलाह दी।

(एक्शन- भारतीय रिजर्व बैंक एवं समस्त बैंक)

- डॉ.रामेश्वर उराँव ने बताया कि पहले झारखंड राज्य में मोटे अनाज की खेती हुआ करती थी। उन्होंने आगे और राज्य उसी खेती के लिए जाना जाता था ,क्योंकि राज्य में पहले से ही वर्षा की कमी थी, लेकिन अब राज्य की बड़ी आबादी धान की खेती की ओर बढ़ गई है, जिसके पोषण के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है।

  उन्होंने बताया कि अब कृषि विभाग लोगों को पुनः मोटे अनाज की खेती करने के लिए जागरूक कर रहा है, लेकिन किसानों के पास उपयुक्त फंड की कमी होने के कारण वे इसकी खेती पर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। माननीय मंत्री ने सदस्य बैंकों से आग्रह किया कि वे किसानों को पूंजी उपलब्ध करायें ताकि बाजरा ,मडुआ एवं अन्य मोटे अनाजों की खेती की जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा लाह की खेती पर किये गये विचार-विमर्श का जिक्र करते हुए डॉ.रामेश्वर उराँव ने कहा कि पहले राज्य के लोग लाह की खेती भी किया करते थे, किन्तु 1960 के बाद कुछ समीकरण बदले जिसकी वजह से लाह की खेती में कमी होने लगी। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि अब चूँकि लोग लाख की खेती की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, बैंकों को राज्ये लोगों की आजीविका और राज्य के विकास के लिए लाह की खेती के लिए वित्त पोषण करने की आवश्यकता है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- डॉ. उराँव ने झारखंड राज्य में छात्रों के खाता खोलने पर अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा द्वारा दिये गये भाषण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बैंकों को छात्रों का खाता खोलने के लिए कोई योजना बनानी होगी ताकि सभी छात्र के खाते खुल सकें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- डॉ. रामेश्वर उराँव ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ऋण का मुद्दा उठाया और उल्लेख किया कि आजीविका पैदा करने के लिए उनके लिए ऋण समय की मांग है। उन्होंने आगे कहा कि सीएनटी/एसपीटी एक्ट के कारण बैंक उन्हें ऋण देने में असमर्थ हैं. हालाँकि, राज्य सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि बैंक सीएनटी/एसपीटी एक्ट की संपत्ति को बंधक बनाकर कैसे वित्त पोषण कर सकते हैं।

  माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि उपरोक्त एजेंडे पर बैठक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए, उनमें से एक था कि यदि बैंक संपत्ति के बदले ऋण प्रदान करता है और उधारकर्ता बैंक देनदारी का भुगतान करने में चूक करता है, तो उस स्थिति में भूमि की बिक्री के समय राज्य सरकार उक्त भूमि को किसी अन्य आदिवासी को बंदोबस्त कर उक्त देनदारी को बैंक द्वारा बंद किया जा सकता है।

  माननीय वित्त मंत्री ने आगे कहा कि दूसरा रास्ता यह है कि लीज अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया जाए। हालाँकि, उन्होने ने कहा की ये केवल चर्चा में हैं और क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अपनी संपत्ति गिरवी रखकर ऋण नहीं ले सकते हैं, इसलिए वे मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं, इस पर डॉ. रामेश्वर उराँव ने सभी सदस्य बैंकों से इन लोगों को ऋण प्रदान करने का अनुरोध किया साथ ही साथ कहा की इस मुद्दे पर राज्य सरकार को भी ध्यान देने की अवशकता है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

छ) कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, श्री सुब्रत कुमार का सम्बोधन

- कार्यपालक निदेशक, श्री सुब्रत कुमार ने 85वी एस.एल.बी.सी सभा में बुलाये जाने पर अपनी खुशी जाहिर की और बताया की हम सभी आज यहाँ एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका ध्येय हमारे देश का समेकित विकास करना है और मुख्यतः कृषकों और ग्रामीण इलाकों में बसे हुए लोगों की आर्थिक स्थिति को मज़बूती प्रदान कर है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया ने झारखंड राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख उक्त पटल से किया ।उन्होने बताया की झारखंड सरकार की कृषि ऋण माफी योजना के तहत आठ लाख STANDARD KCC ऋणी किसानों को चिन्नहित किया गया एवं इनमे से लगभग साढ़े चार लाख किसानों को DBT के माध्यम से करीब अठारह सौ करोड़ रूपय का भुगतान अब तक किया जा चुका है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री सुब्रत कुमार ने बताया की झारखंड सरकार द्वारा ,राज्य के सभी बिरसा किसानों को ,KCC ऋण से आच्छदित करने के लिये राज्य में सघन अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत 13.77 लाख मौजूदा KCC लाभार्थियों के अतिरिक्त अब तक 6.50 लाख नए कृषकों को भी बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया गया है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री कुमार ने कहा की झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ KCC ऋण के PROMPT REPAYMENT पर राज्य सरकार द्वारा तीन प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाता है और यह केंद्र सरकार के तीन प्रतिशत के अनुदान के अतिरिक्त है। उन्होने प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा दिये गए उनके सम्बोधन का ज़िक्र करते हुए कहा की राज्य सरकार इस योजना में सुधार ला रही है और अतिरिक्त एक प्रतिशत का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रदान करेगी जो राज्य के किसानो के लिए एक बड़ा कदम है।

  श्री कुमार ने सभी बैंक के राज्य प्रमुख एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों से आग्रह किया कि इस योजाना का प्रसार व्यापक स्तर पर करें ताकि अधिक से अधिक किसान PROMPT REPAYMENT कर इस योजना का लाभ उठा सकें।

(एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- कार्यपालक निदेशक ने सभा को विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में बताया। उन्होने कहा की इस यात्रा का शुभारंभ माननीय प्रधान मंत्री के द्वारा 15 नवंबर, 2023 को झारखंड राज्य के खूंटी जिले से किया गया। श्री कुमार ने बताया की झारखंड राज्य के नौ जिलों से प्रारम्भ हुई इस यात्रा का विस्तार सभी 24 जिलों तक किया जाना है और इस यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर कैंपों के माध्यम से अन्य सुविधाओं के साथ, बैंकिंग सुविधाएँ जैसे घर घर केसीसी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना इत्यादि को भी जनमानस तक पहुंचानी है।

  उन्होने इस अभियान के अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं एल.डी.एम की विशेष भूमिका बताई अथवा इस जनकल्याणकारी अभियान को वृहद स्तर पर चलाने और सफल बनाने का आग्रह किया।

(एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री कुमार ने घर घर केसीसी को राज्य के लिए एक अहम अभियान बताया। उन्होने कहा की 01 अक्टूबर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक चलाये जा रहे इस अभियान के अंतर्गत यह सुनिश्चित करना है कि सभी **पीएम किसान** लभार्तियो तक केसीसी ऋण पहुँच सके। उन्होने नाबार्ड, राज्य कृषि एवं पशुपालन विभाग एवं अन्य हितधारकों से अनुरोध किया कि वे इस अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

  उन्होने आगे कहा की इस अभियान के अंतर्गत अब तक कि प्रगति संतोषजनक नहीं है एवं उन्होने सभी बैंक प्रमुखो व अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से आग्रह किया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र की शाखाओ को सक्रिय करें और उन्हे प्रोत्साहित करें कि कोई भी पीएम किसान लाभार्थी केसीसी ऋण से वंचित ना रह जाए।

  (एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- कार्यपालक निदेशक, श्री सुब्रत कुमार ने अपने वक्तव्य में 17 सितम्बर, 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम विश्वकर्म योजना के शुभारंभ होने के बारे में सभा को बताया। उन्होने आगे बताया कि इस योजना के तहत 18 पारंपरिक पेशों से जुड़े कारीगरों का चयन कर पांच से सात दिन का प्रशिक्षण एवं टूल किट प्रदान किया जाना है तत्पश्चात **बुनियादी प्रशिक्षण** पप्राप्त विश्वकर्मा को, बैंकों द्वारा प्रथम चरण में 1.00 लाख रूपय तक के ऋण का प्रावधान है। उन्होने बैंको से आग्रह किया कि वे इस योजना का लाभ झारखंड राज्य के पात्र जनसख्या तक पहुचाए।

  (एक्शन-समस्त बैंक)

- श्री सुब्रत कुमार ने सदन को सितम्बर तिमाही में बैंकों द्वारा प्राप्त प्रमुख उपलब्धि के बारे में बताया:
  - श्री कुमार ने बताया कि सितंबर तिमाही के दौरान राज्य के कुल जमा राशि में 13640.61 करोड़ रूपय कि वृद्धी दर्ज की गायी है जो कि पिछली तिमाही से 4.43 प्रतिशत अधिक है।
  - आगे उन्होने कहा कि राज्य के कुल ऋण में सितंबर तिमाही के दौरान 6669.13 करोड़ रूपय कि वृद्धी दर्ज की गायी है जो कि पिछली तिमाही से 5.82 प्रतिशत अधिक है।
  - कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि राज्य में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सितंबर तिमाही के दौरान 20560 नए STREET VENDORS को राज्य के बैंकों द्वारा ऋण वितरण किया गया, जो कि पिछली तिमाही की अपेक्षा पचास प्रतिशत से भी अधिक है। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि वे ये गति बनाए रखें।

  (एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- अंत में श्री कुमार ने सभी वक्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं का उल्लेख किया और उन्हें आश्वस्त किया कि चर्चा किए गए सभी मूल्यवान बिंदुओं पर राज्य के बैंक कार्य करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने साइबर धोखाधड़ी पर माननीय वित्त मंत्री द्वारा कही गई बहुमूल्य बात का भी उल्लेख किया और सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे ग्राहकों के साथ-साथ बैंक कर्मचारियों को भी इस बारे में अच्छी तरह से जागरूक करें और इस समस्या के उचित समाधान के बारे में भी कर्मचारियों व ग्राहकों को जागरुक करें।

  उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक और सभी बैंकों से शिविर के माध्यम से लोगों को वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूक करने का आग्रह किया।

  (एक्शन- भारतीय रिजर्व बैंक एवं समस्त बैंक)

इस सम्बोधन के उपरांत एस.एल.बी.सी के वरीय प्रबन्धक, श्री रोशन चौधरी द्वारा एस.एल.बी.सी बैठक के व्यवसायिक सत्र का संचालन किया गया, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा एजेंडावार विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों के प्रदर्शन पर चर्चा की गई। व्यावसायिक सत्र के दौरान हुई कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएँ इस प्रकार थीं:

- सत्र के दौरान ब्रिक और मोर्टर शाखाओं की लंबितता के मुद्दे पर चर्चा की गई, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप महाप्रबंधक, श्री बिनोद बिहारी मिश्रा ने व्यक्तिगत रूप से राज्य प्रमुखों से उपरोक्त मुद्दे पर अंतिम तिथि प्रदान करने का आग्रह किया जिसपर निम्न जवाब राज्य प्रमुखो द्वारा दिया गया:

i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (परती कुसवानी) के महाप्रबंधक ने 25th जनवरी, 2024 तक खुलने की बात बताई।

ii) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (हरदाग कलन) के उप महाप्रबंधक ने 31st दिसम्बर, 2023 तक शाखा खुलने की बात बताई।

iii) बैंक ऑफ महाराष्ट्रा (मजने) की सहायक महाप्रबंधक ने बताया की पंचायत भवन में आवंटित क्षेत्र में जगह की कमी (280 वर्ग फुट) के कारण बैंक शाखा खोलना संभव नहीं है, बैंक ने लॉबी के क्षेत्र प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही अथवा बैंक इस वर्ष 31 दिसंबर तक शाखा खोलने का लक्ष्य रखा है।

iv) आईडीबीआई बैंक (सोने हरा) की तरफ से बताया गया की चिन्हित परिसर में उचित निर्माण न होने के कारण बैंक को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी बैंक इसे 31 दिसंबर तक खोलने का प्रयास करेंगे।

v) इंडसइंड बैंक (करके) की तरफ से 31 दिसम्बर तक शाखा खोलने की बात बताई गयी।

vi) यूको बैंक (झिमरी) के सहायक महाप्रबंधक ने बताया की बैंक 31 दिसम्बर तक शाखा खोलने की बात बताई गयी हालाकी उन्होने बताया कि संबंधित बीडीओ को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए समझौता नहीं हो पा रहा है अथवा उन्होंने राज्य सरकार और एलडीएम से इस संबंध में प्रशासन को अपडेट करने का अनुरोध किया, ताकि समय पर शाखा खोली जा सके।

(एक्शन-UBI, CBI, BOM, IDBI, INDUSIND & UCO)

अंत में, एसएलबीसी के उप महाप्रबंधक श्री अनिल जगदीश जाधव ने एस.एल.बी.सी की 85वीं बैठक में शामिल सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। सभा का संचालन श्रीमती प्राची मिश्रा,प्रबन्धक, रा. स्त. बै. स द्वारा किया गया।

(मनोज कुमार)
महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.

85 वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठक ,झारखंड

29 नवंबर 2023 होटल रेडिसन ब्लू, कडरू बाई पास रोड, रांची

क्रमांक	नाम	पद	विभाग	संपर्क
1	डॉ० रामेश्वर उराँव	माननीय वित्त मंत्री	झारखंड राज्य सरकार	
2	श्री अजय कुमार सिंह	प्रधान सचिव	वित्त विभाग, झारखंड राज्य सरकार	
3	श्री सुव्रत कुमार	कार्यकारी निदेशक	बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय	
4	श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह	क्षेत्रीय निदेशक	भारतीय रिजर्व बैंक	
5	श्री सुनील कृष्ण जहागीरदार	मुख्य महाप्रबंधक	नाबार्ड	
6	श्री रमेश घोलप (आई.ए.एस)	संयुक्त सचिव	वित्त विभाग, भारत सरकार	9583390555
7	श्री सैयद रियाज़ (आई.ए.एस)	अवर सचिव	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,रांची	9599553592
8	श्री बिनोद बिहारी मिश्रा	उप महाप्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	9538323290
9	श्री मनोज कुमार	महाप्रबंधक	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	9099915122
10	श्री अनिल जगदीश जाधव	उप महाप्रबंधक	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	9011060913
11	श्री सनी	प्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	8809501850
12	श्री सुमन साहू	उप महाप्रबंधक	नाबार्ड	9438125625
13	श्री प्रभास बोस	महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9669288085
14	श्री बैजनाथ सिंह	महाप्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9162487223
15	श्री श्रीनाथ जोशी	महाप्रबंधक	केनरा बैंक	9334913525
16	श्री देवेश मित्तल	उप महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9971981001
17	श्री एफ आर बुखारी	उप महाप्रबंधक	इंडियन बैंक	9051658238
18	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	उप महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	9958999735
19	श्री सुनील कुमार	उप महाप्रबंधक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9264291876
20	श्री मदन मोहन बरियार	चेयरमैन	झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक	9304118032
21	श्री आदित्य आहुवालिया	पीएमयू	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,रांची	7016182489
22	श्री संजीव कुमार सिंह	उप महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया	9769118862
23	श्री इंद्रजीत यादव	संयुक्त निदेशक	एमएसएमई-डीएफओ रांची	8126248984
24	श्री परिषेष पाठक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	9835191053
25	श्री पवन कुमार	सहायक महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	9831720610
26	श्री पुष्कर भगत	प्रबंधक लेखा(कार्यवाहक सीईओ)	धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक	9693595573
27	श्री रमन श्रीवास्तव	सीटीओ	धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक	9798027478
28	श्री प्रदीप कुमार हजारी	विशेष सचिव सह सलाहकार	कृषि विभाग	9441821911
29	डॉ० रजनी पुष्पा सिन्हा	संयुक्त निदेशक	पशुपालन झारखण्ड सरकार	9431352364
30	डॉ० विवेक कुमार सिन्हा	उप निदेशक	पशुपालन झारखण्ड सरकार	7677761001
31	श्रीमती पुनम रानी	एमआईएस मैनेजर	एसपीएमयू, पीएमएफएमई, उद्योग विभाग	7004964481
32	डॉ० एच.एन.द्विवेदी	निदेशक	मत्स्य पालन विभाग,झारखंड सरकार	9835210462
33	श्री शंभू प्रसाद यादव	उप निदेशक	मत्स्य पालन विभाग,झारखंड सरकार	7903097749
34	श्री विश्वजीत कुमार सिन्हा	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	7718825815
35	श्री संजय कुमार	सहायक महाप्रबंधक	झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक	8709316664
36	श्री शंकर महतो	सहायक महाप्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	6287395610
37	श्रीमती शिखा कुमारी	आंचलिक प्रमुख	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9971149208
38	मेजर विक्रांत टंडन (सेवानिवृत्त)	आंचलिक प्रबंधक	यूको बैंक	9928635906
39	श्री जी पी सिंह	अवर सचिव	उद्योग विभाग	9934536475
40	श्री धीरेन्द्र मिश्रा	मंत्री के पीए	झारखंड सरकार	8340466640
41	डॉ अनमोल कुमार लाल	उप निदेशक	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,झारखण्ड सरकार	7654299691
42	श्री स्वप्नेश दास	सलाहकार	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,झारखण्ड सरकार	7978706979
43	श्रीमती रीता तिर्की	खाता अधिकारी	शिक्षा (जेईपीसी)	8789054886
44	श्री राजीव कुमार	सहायक निदेशक	केवीआईसी	9474059775
45	श्री एस बी मिश्रा	एसडीआर	राज्य निदेशक रसेटी	9330752100
46	श्री अनिल कुमार	एसएनओ आरसेटी	जेएसएलपीएस	9431901016
47	श्री राजेश गुप्ता	पीएम-एफआई	जेएसएलपीएस	9893420782
48	श्री बिष्णु सी परिदा	मुख्य परिचालन अधिकारी	जेएसएलपीएस (आरडीपी जीओजे)	9939221549
49	श्री चंद्र भूषण पांडे	राज्य नियंत्रक	राष्ट्रीय अकादमी,रुडसेटी	9073396646
50	श्री मुकुल पी एक्का	सहायक महाप्रबंधक	सिडबी	7759811384
51	श्री शिवम सिंह	माननीय सचिव	झारखंड लघु उद्योग संघ (जेएसआईए)	9835334399
52	श्री राजीव रंजन	वरिष्ठ प्रबंधक	इंडियन बैंक	8517763005
53	श्री प्रताप होरो	वरिष्ठ प्रबंधक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9047724477
54	श्री राजीव रंजन	मुख्य प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9073369980

55	श्री हरिचंद मुर्मू	वरिष्ठ प्रबंधक	यूको बैंक	9792301920
56	श्री सुदीप्तो कुमार सिन्हा	मुख्य प्रबंधक	इंडियन ओवरसीज बैंक	9028147750
57	श्री रोहित कुमार	मुख्य प्रबंधक	पंजाब एंड सिंध बैंक	8437019190
58	श्री पंकज कुमार	उप महाप्रबंधक	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	9892918208
59	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह	प्रबंधक	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	7909087034
60	श्रीमती तनुश्री अग्रवाल	सहायक प्रबंधक	फ़ेडरल बैंक लिमिटेड	7992406277
61	श्री नवनीत गांधी	उप उपाध्यक्ष	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	9934011083
62	श्री कौशल किशोर	सहायक महाप्रबंधक	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9934313934
63	श्री राजेश कुमार	सहायक शाखा प्रबंधक	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	
64	श्री आकाश कुमार	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	एक्सिस बैंक लिमिटेड	9004098940
65	श्री प्रीतम सिन्हा	सहायक उपाध्यक्ष	एक्सिस बैंक लिमिटेड	7231855238
66	श्री राज कुमार कमल	आरएच	इंडसइंड बैंक	9304143093
67	श्री फेहाद अहमद शाह	प्रबंधक	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	9596387070
68	श्री रबी कुमार पांडे	उपाध्यक्ष	यस बैंक	9434383189
69	श्री कमल चौधरी	वरिष्ठ प्रबंधक	कोटक महेंद्र बैंक लिमिटेड,	9386802023
70	श्री अरुण कुमार मोहन	प्रबंधक	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	9048874928
71	श्रीमती ज्योति कुमारी	प्रबंधक	डीबीएस बैंक	7547088880
72	श्री वी विजय कुमार	प्रबंधक	करूर वैश्य बैंक	9505163878
73	श्री स्नेह सौरभ	राज्य प्रमुख सरकारी व्यवसाय	बंधन बैंक	8340639507
74	श्री रॉबिन वर्मा	वरिष्ठ प्रबंधक	ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड	7004756456
75	श्री रवि शंकर	वितरण प्रबंधक	उज्जीवन लघु वित्त बैंक	7781003289
76	श्री अमरेन्द्र झा	आंचलिक प्रमुख	उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड	9334616474
77	श्री प्रवीण कुमार ओझा	शाखा प्रबंधक	जाना लघु वित्त बैंक	7004940734
78	श्री मुकेश कुमार मिश्रा	ए.बी.पी और शाखा प्रबंधक	ए यू लघु वित्त बैंक	9835474216
79	श्री विनायक पाटिल	ए.बी.पी	एयरटेल पेमेंट बैंक	9890999888
80	श्री अशोक कुमार पांडे	उपाध्यक्ष	फिनो पेमेंट बैंक	7566668649
81	श्री बिरज डेका	मुख्य प्रबंधक	इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक	9038224956
82	श्री विकास कुमार	राज्य प्रमुख	पेटीएम पेमेंट बैंक	7004657014
83	श्री देवव्रत शर्मा	चतरा	अग्रणी जिला प्रबंधक	8002738027
84	श्री राजीव कुमार	देवघर	अग्रणी जिला प्रबंधक	8406002014
85	श्री अमित कुमार	धनबाद	अग्रणी जिला प्रबंधक	8298715715
86	श्री चन्द्रशेखर पटेल	दुमका	अग्रणी जिला प्रबंधक	7488060045
87	श्री संतोष कुमार	पूर्वी सिंहभूम	अग्रणी जिला प्रबंधक	8600500542
88	श्री ए के मांझी	गढ़वा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7209822572
89	श्री चंदन चौहान	गोड्डा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9534741185
90	श्री पवन कुमार	गुमला	अग्रणी जिला प्रबंधक	889743105
91	श्री राकेश आजाद	हजारीबाग	अग्रणी जिला प्रबंधक	8709551260
92	श्री राजीव कुमार मंदिलवार	लातेहार	अग्रणी जिला प्रबंधक	8936802753
93	श्री नेविन्दु कुमार	लोहरदगा	अग्रणी जिला प्रबंधक	8177819118
94	श्री एंथोनी लियांगी	पलामू	अग्रणी जिला प्रबंधक	7992310119
95	श्री संजीव कुमार	रामगढ़	अग्रणी जिला प्रबंधक	9934363709
96	श्री श्रीकांत	रांची	अग्रणी जिला प्रबंधक	9470650026
97	श्री बीरेंद्र केआर शिट	सरायेकेला खरसावा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9771438410
98	श्री दिवाकर सिन्हा	पश्चिम सिंहभूम	अग्रणी जिला प्रबंधक	9771438409
99	श्रीमती सुनीता कुमारी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
100	श्रीमती एकता उपाध्या	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
101	श्री रोशन चौधरी	राज्य,स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9431787051
102	श्रीमती प्राची मिश्रा	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9931399824
103	श्रीमती दर्पण शर्मा	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
104	श्री कुमार ऋषव	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9525166838
105	श्री प्रशांत कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9471182910
106	श्री प्रदीप चटर्जी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
107	श्री शैलेश कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	8005958455
108	श्री बिट्टू कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	